Peace Progress Democracy

Price Rs. 1

Students POST

Member
International Union
of Students

ALL INDIA STUDENTS BLOC (AISB)

(Originally Founded in 1936)*

A monthly news magazine of AISB

Volume 1 Issue 1 Monthly July 2009

विदेशी शिक्षण संस्थान (एफ.ई.आई.) विधेयक भारत को उच्च शिक्षा से दूर करेगा

जैसा कि आजकल हम सभी विभिन्न समाचार पत्रों और न्यूज चैनलों के माध्यम से जान रहे है कि हमारी केन्द्रीय सरकार उच्च शिक्षा में विदेशी निवेश लाने की तैयारी कर रही है। यह सोच भारत सरकार की आत्मघाती कदम है।

हमारे मानव संसाधन विकास मंत्री श्री कपिल सिब्बल ने 29 मई को पद संभालने के बाद घोषणा की लम्बित पड़े विदेशी शिक्षण संस्थान (एफ.ई.आई.) विधेयक को वे उच्च प्राथमिकता देंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय इस विधेयक का समर्थन कर रहा है। यह विदेशी शिक्षण संस्थान विधेयक 2007 को मई 2007 के पहले सप्ताह से राज्य सभा में पेश करने की योजना थी लेकिन वाम पार्टियों के विरोध के फलस्वरूप अंतिम क्षणों में इसे वापस ले लिया था। कपिल सिब्बल जो उस समय विज्ञान और तकनीकी मंत्री थे, इस विधेयक को आगे बढ़ा रहे थे। इस विधेयक को वापस लिये जाने के बाद उन्होंने कहा था कि "हम अपने शिक्षा क्षेत्र को विदेशी विश्वविद्यालय के लिये खोलने जा रहे है और यह भारी (एफ.डी.आई.) कमाने वालों में एक होगा"। अमेरिका के वाल स्ट्रीट जर्नल ने 11 जून 2009 को अपने अंक में लिखा है कि "विदेशी कॉलेजों पर प्रतिबन्धों को हल्का करने के भारतीय राजनीतिज्ञों के हाल के प्रयासों को वामपंथियों ने रोक दिया था, जिनका कहना था कि शिक्षा की लागत बढ़ने से गरीब लोग पीछे रह जायेंगे। लेकिन भारत की नयी गठबंधन सरकार ने पिछले सप्ताह ही सत्ता ग्रहण किया है, वह वामपंथियों पर निर्भर नहीं है और इससे मिस्टर सिब्बल के प्रयासों के सफल होने के अवसर बढ़ रहे हैं।" पत्रिका ने सिब्बल को यह कहते हुये बताया है कि "मुझे उम्मीद है 2010 तक दुनिया भर के विश्वविद्यालय भारत की ओर दौर करेंगे और इसलिये वे इस बाजार को खोलना चाहते है।

आज हम सभी इस बात को जानते है कि दर्जनों फर्जी संस्थान हमारे देश में चल रहे हैं परन्तु सरकार जानबुझकर छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है और वैसे संस्थानों के ऊपर कोई कार्यवाही नहीं हो रही है। अभी 10 जून 2009 को ऑल इण्डिया काउन्सिल फॉर टेक्निनल एजूकेशन की वेबसाइट पर एक विज्ञापन था विज्ञापन संख्या AICTE/legal/03(01)/2006-07 में छात्रों को यह सूचना दी गयी है।

"आज तक उपलब्ध सूचना के अनुसार ही तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में कोर्स चला रहे हैं। आज तक उपलब्ध सूचना के अनुसार ऐसे 169 संस्थान पाये गये जो AICTE की मंजूरी हासिल किये बिना ही तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में कोर्स चला रहे हैं। ऐसे 104 संस्थान है जो AICTE की मंजूरी के बिना विदेशी विश्वविद्यालय के साथ मिलकर तकनीकी कार्यालय चला रहे हैं। छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे AICTE की मंजूरी के बिना किसी भी संस्थान द्वारा चलाये जा रहे तकनीकी शिक्षा कोर्सों में दाखिला न लें। उन्हें आगाह किया जाता है कि जिन कार्यक्रमों को मंजूरी नहीं मिली है उनमें दाखिला लेने के रोजगार, उच्च शिक्षा आदि में योग्यता के मामले में गंभीर परिणाम हो सकते है। इस विज्ञापन के नीचे दो वेबलिंक दिये गये है जिनमें ऐसे गैर मंजूरी शुदा संस्थानों की सूचियाँ दी गयी है। स्तब्ध कर देने वाली बात यह है कि इन सूचियों में ICFAI, ICPM अंसल इंस्टीट्यूट ऑफ टैक्नॉलोजी और जीडी गोयनका वर्ल्ड इंस्टीच्यूट जैसे संस्थान शामिल है। जो अपे कार्यक्रमों और विदेशी विश्वविद्यालयों के साथ अपने सम्बन्ध के बारे में भी दैनिक अखबारों में प्रथम पेज पर पूरे–पूरे पेज के विज्ञापन छपवाते हैं। केन्द्रिय मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने अब तक कोई कार्यवाही ऐसे संस्थानों पर क्यों नहीं कि। **इसका अंदाजा इस लेख के पाठक खूद लगा सकते है।**

भारत की अमेरिका के साथ कूटनीतिक भागीदारी का विस्तार रक्षा से बढ़ते हुये सुरक्षा तक वाणिज्य से शिक्षा तक बढ़ता जा रहा है। प्रस्तावित "शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग" इस क्षेत्र में भारत की सर्वमान्य श्रेष्ठता को अन्तर्राष्ट्रीय मंच पर नीचा दिखाने की एक गहरी साजिश है।

11 जून 2009 को दिल्ली में देश के मानव संसाधन विकास मंत्री कपिल सिब्बल और अमेरिकी अवर सचिव (राजनैतिक मामले) की

बैठक हुयी, जिसमें दोनों देशों के बीच शिक्षा के क्षेत्र में विस्तार की योजनाओं पर नजर रखने के लिये संयुक्त कार्यकारी समूह के गठन की घोषणा की गयी।

इस सबसे आगे बढ़ते हुये सबसे खतरनाक घोषणा 9 जुलाई 2009 को कपिल सिब्बल जी ने पेरिस में, जहाँ UNESCO का प्रधान कार्यालय है, एक सेमिनार में जो उच्च शिक्षा पर था घोषणा कर दिया कि कांग्रेस नीत यूपीए सरकार भारतीय उच्च शिक्षा को विदेशी शिक्षा निवेशक और निजी लोगों को देने के लिये बिल्कुल वचनवद्ध है। इससे पहले पीछले सप्ताह संसद में मंत्री जी ने कहा कि कांग्रेस सरकार बहुत जल्द एक विधेयक लायेगी जिससे भारत में विदेशी विश्वविद्यालय का कैंपस खोलना बिल्कुल आसान हो जायेगा।

हम लोग साधारण तौर से यह देख रहे हैं कि अपने देश में प्राईवेट स्कूल खुलने से सरकारी स्कुल की स्थिति खराब हो गयी। विदेशी हस्तक्षेप उच्च शिक्षा में होने से देश का शिक्षा व्यवस्था चौपट हो जायेगी और नागरिकों में पूर्ण गुलामी की मानसिकता हो जायेगी।

जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि देश में सांस्कृतिक प्रदूषण (Cultural Pollution) पश्चिमी देश फैला रहे है। जिसमें राष्ट्र भक्ति में कमी आ रही है, नैतिक मूल्य खत्म हो रहे है।

ऐसे समय में यह उच्च शिक्षा में विदेशी निवेश बहुत ही खतरनाक है इससे देश मानसिक और आर्थिक रूप से गुलाम हो जायेगा। उच्च शिक्षा मुहैया कराना सरकार का प्रमुख कार्य है। यह सरकारी पैसे से होना चाहिये। एक तरफ सरकार कहती है हमारे पास बहुत विदेशी मुद्रा भण्डार है तो इस पैसे से क्यों नहीं उच्च शिक्षा को दुरूस्त किया जा रहा है।। यह बात छात्रों को जानने का हक है।

सरकार हर कार्य प्राईवेट लोग/संस्थान से कराना चाहती है अगर हर कार्य प्राईवेट लोग/संस्थान करेगा तो सरकार क्या करेगी।

इस सबसे तो अच्छा होता कि सरकार चलाने का कार्य ही किसी प्राईवेट यह मल्टीनेशनल कम्पनी को दे देना चाहिये। आज के इस परिप्रेक्ष्य में छात्रों, अभिवावकों और देश के बारे में सोचने वाले नागरिकों का यह नितांत कर्तव्य है कि इस पर गंभीरता से सोचे और इसका विरोध करे अन्यथा फिर से आजादी के 60 साल बाद हमारी मातृभुमि फिर से गुलाम हो जायेगी।

अमरेश कुमार (राष्ट्रीय महासचिव ए.आई.एस.बी.)

स्टूडेन्ट्स ब्लॉक की संक्षिप्त पृष्ठभूमि

भारत के लम्बे स्वतंत्रता संग्राम की विरासत से स्टूडैन्ट्स ब्लॉक का जन्म हुआ तथा देश के अग्रणी स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के नेतृत्व में स्टूडैन्ट्स ब्लॉक द्वारा सक्रियतापूर्वक देश को विदेशी अंग्रेज सरकार से आजाद कराने में, स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लिया। वस्तुत: देश के महानतम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी नेताजी सुभाष चन्द्र बोस के प्रयास तथा क्रांतिकारी प्रेरणा से ही स्टूडैन्ट्स ब्लॉक की स्थापना 1939 के द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान सुभाष चन्द्र बोस द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में देश के समस्त छात्र वर्ग के देशभक्त राष्ट्रवादी विचारधारा युक्त छात्रों के इस साझे मंच में द्वितीय विश्व युद्ध के प्रति देश की जनता द्वारा लिये जाने वाले रूख के बारे में परस्पर विरोधी विचार उत्पन्न होने लगे तो तब राष्ट्रवादी विचारधारा युक्त छात्रों द्वारा संगठित होकर अपना पृथक ऑल इण्डिया स्टूडैन्ट्स फैडरेशन (राष्ट्रवादी) नामक अपना पृथक छात्र संगठन बना लिया। इस प्रकार यह ऑल इण्डिया स्टूडैन्ट्स फैडरेशन (राष्ट्रवादी) अपने पृथक गठन के तत्काल बाद ही देश को अंग्रेजों से आजाद कराने के लिये साम्राज्यवाद विरोधी स्वतंत्रता संग्राम में और जी जान से सक्रिय होकर जुट गया। इस प्रकार देश को साम्राज्यवादी ब्रिटिश सरकार से आजाद कराने के अपने साम्राज्यवाद विरोधी सक्रियता के कारण ब्रिटिश सरकार द्वारा ऑल इण्डिया स्टूडैन्ट्स फैडरेशन (राष्ट्रवादी) पर प्रतिबंध लगा दिया गया। 1945 में जब यह प्रतिबंध इस पर से हटा लिया गया एवम् इसके सभी छात्र नेता जेलों से रिहा कर दिये गये तब 1945 में बंबई में हुये अपने अधिवेशन में ऑल इण्डिया स्टूडैन्ट्स फैडरेशन (राष्ट्रवादी) का नाम बदलकर ऑल इण्डिया स्टूडैन्ट्स ब्लॉक कर दिया गया।

इस प्रकार 1951 में अपने औपचारिक गठन के बाद से ही ऑल इण्डिया स्टूडैन्ट्स ब्लॉक नेताजी सुभाष चन्द्र बोस द्वारा दिखाये मार्ग पर चलकर नेताजी के विचारों के आधार पर देश के छात्र आन्दोलन का संचालन कर रहा है। नेताजी सुभाष चन्द्र बोस की विचारधारा पर चलकर स्टूडैन्ट्स ब्लॉक तथा इसके पूर्ववर्ती छात्र संगठनों के क्रांतिकारी छात्रों द्वारा भारी संख्या में स्वतंत्रता संग्राम में अपनी भागीदारी करके पुलिस उत्पीड़न को सहकर भी विभिन्न विरोधी तरीकों को अपनाकर आजादी की लड़ाई जारी रखा। छात्र ब्लॉक के नेतृत्व में आजादी की लड़ाई में बहुत से छात्रों को जेल जाना पड़ा तथा बहुत छात्र शहीद भी हो गये।

पिछली शताब्दी के चौथे दशक के अंत में छात्र ब्लॉक द्वारा व्यापक पैमाने पर छात्र आन्दोलनों का संचालन किया गया।

देश की आजादी के बाद भी छात्र ब्लॉक आन्दोलनों में अग्रणी रहा है। इसके साथ-साथ ए.आई.एस.बी. अपना यह परम् अहम कर्तव्य समझता है कि वह देश के सभी जनतांत्रिक आन्दोलनों तथा विश्व शांति आन्दोलन में अग्रणी रहे। ए.आई.एस.बी. का यह विश्वास है कि एक बेहतर समाज बनाने के लिये सह सभी प्रकार के अन्यायों तथा विकासशील देश की जनता के न्यायपूर्ण संघर्ष के पक्ष में अपना सक्रिय समर्थन प्रदान करके संघर्षशील रहे। तीसरी दुनिया के विकासशील गरीब देशों में नये उत्पन्न हो रहे नव-उपनिवेशवाद इस संबंध में उल्लेखनीय है तथा ए.आई.एस.बी. महसूस करता है कि यह नव-उपनिवेशवाद स्वतंत्रता तथा जनतंत्र हेतु एक गंभीर खतरा है।

ऑल इण्डिया स्टूडैन्ट्स ब्लॉक (ए.आई.एस.बी.) 1951 में अपने गठन के बाद से सदैव ही देश का एक अग्रणी क्रांतिकारी विद्यार्थी संगठन रहा है। यह संगठन 1951 से ही भारत के छात्रों तथा युवकों में राष्ट्रभक्ति तथा समाजवादी कार्यक्रमों के आधार पर करता चला आया है। स्टूडैन्ट्स ब्लॉक देश में एक ऐसे पूर्ण समाजवादी जनतंत्र की स्थापना के लक्ष्य को प्राप्त करना चाहता है जिसमें कि भारत के छात्रों, किसानों तथा गरीबों के सामाजिक, आर्थिक तथा राजनैतिक मूल अधिकार सुरक्षित रखे जा सकेंगे।

संगठन के इतिहास के पन्नों से

इतिहास के गर्भ में 1939-40 और वर्तमान के 2009-10 में समानता

आज से करीब 70 साल पहले 19 मार्च 1940 को महान क्रांतिकारी नेता देशभक्त नेताजी सुभाष चन्द्र बोस ने रामगढ़ में आयोजित समझौता विरोधी सम्मेलन की अध्यक्षता की थी। इस सम्मेलन के माध्यम से देश को 'साम्राज्यवाद के खिलाफ समझौताहीन संघर्ष' का आह्वान किया था।

अगर हम आजादी पूर्व के द्वितीय विश्वयुद्ध के दौरान (1939-40) के संघर्षमय दिनों की तुलना आज (2009-10) से करने बैठे तो सप्रमाण पाते हैं कि आज की सबसे बड़ी साम्राज्यवादी ताकत अमेरिका की वर्चस्व वाली दुनिया में तथाकथित अपनी आजादी को छोड़कर तब से स्थितियों में कोई भिन्नता नहीं है। हमारा देश एक बार फिर उसी तरह साम्राज्यवाद का शिकार होने के कगार पर है जैसा उस समय हुआ था। इसलिए, आज के समय में एक बार फिर यह प्रासंगिक हो गया है कि हम 1940 में रामगढ़ में हुए समझौतावाद विरोधी सम्मेलन की भावना को जाग्रत करें, भले ही सामाजिक-राजनीतिक परिस्थितियों और रणनीति में कुछ बदलाव आ गया हो या करना पड़े।

1939-40 के दौरान मूल प्रश्न यह था कि हम कैसे ब्रिटिश साम्राज्यवाद के खिलाफ संघर्ष करें और अपनी आजादी को प्राप्त करें। 2009-10 में प्रश्न यह है कि कैसे हम केंद्र की कांग्रेस नीत सरकार की उन नीतियों के खिलाफ संघर्ष करें, जिन नीतियों के कारण हमारा देश आज की दुनिया में साम्राज्यवादी-पूंजीवादी ताकतों का सबसे बड़ा नेता अमेरिका का रणनीतिक साझीदार बनने जा रहा है। यह रणनीतिक साझेदारी हमारी संप्रभुता को तो प्रभावित करेगी ही, हमारी स्वतंत्र विदेश नीति को पूरी तरह चौपट कर देनेवाली है। साम्राज्यवादी वैश्विकरण और निजीकरण की नीतियां हमारी आर्थिक नीतियों को भी संपन्न वर्गो के हित में और जनविरोधी बनानेवाली हैं। हमारी केंद्र की वर्तमान कांग्रेस नीत सरकार से मिलीभगत कर अमेरिका हमारी रक्षा और सुरक्षा व्यवस्था, हमारी अर्थनीति और संस्कृति, हमारी शिक्षा और हमारी पूरी जीवन शैली पर अपना प्रभाव जमाना चाहता हैं।

इस प्रकार हम अमेरिका नीत विपरीत और खतरनाक स्थितियों की ओर बढ़ रहे हैं। जरूरत इस बात की है कि हम इस तरह की नीतियों के खिलाफ एकजुट होकर लड़ें। स्पष्ट तौर पर यह लड़ाई प्रगतिशील ताकतों की एकता के आधार पर ही लड़ी जा सकती है। साम्राज्यवाद के खिलाफ हमारी अंतिम जीत के लिए हमें सुभाष चन्द्र बोस रामगढ़ में किए गए समझौता विहीन संघर्ष के आह्वान की भावना को पुनर्जाग्रत करना होगा। सुभाष ने सही ही कहा था, 'आदमी ज्ञान की खोज में लगा रहता है और जैसे-जैसे उसका अनुभव बढ़ता जाता है, वह महसूस करता है कि यह तथ्य पूरी तरह सत्य है कि इतिहास अपने आप को दोहराता है।'

खुद सुभाष ने अपने अध्यक्षीय भाषण में कहा था, 'रामगढ़ सम्मेलन देश की साम्राज्यवाद से समझौता करनेवाली तमाम ताकतों से लड़ने को कमर कसे सभी साम्राज्यवाद विरोधी ताकतों को प्रोत्साहित करने के प्रति प्रतिबद्ध है।' इन सब के बावजूद कांग्रेस का दक्षिणपंथी धरा आजादी की लड़ाई के दिनों से अब तक हमेशा साम्राज्यवाद से समझौता करता आया है। सुभाष ने रामगढ़ में उचित ही कहा था, 'हमारी गतिविधियां पूरे देश के स्तर पर ऐसे राष्ट्रीय सम्मेलन में उन सब ताकतों पर केंद्रित होनी चाहिए जो साम्राज्यवाद से किसी तरह का समझौता नहीं करने वाले हैं।'

आज की भी सबसे बड़ी जरूरत यही है। और यह काम राष्ट्रवादियों को ही करना होगा। नेताजी ने भी उन्हें 1940 के शुरू में ही सलाह दी थी, 'अगर वे तमाम खतरों, परेशानियों और बाधाओं के बावजूद साम्राज्यवाद के खिलाफ लड़ाई की एक मजबूत और समझौताविहीन नीति बनाते हैं

तो वामपंथी देश में नया इतिहास बना डालेंगे और पूरा भारत वामपंथ के झंडे के नीचे आ जाएगा।'

और अंत में सुभाष ने अपने कदम और अपनी भूमिका को स्पष्ट किया, जिसे वामपंथ के लिए तैयार किया था। रामगढ़ में उन्होंने कहा था, 'भारतीय वामपंथियों को भविष्य में न केवल साम्राज्यवाद के खिलाफ संघर्ष करना होगा बल्कि उन्हें इसके भारतीय सहयोगियों के खिलाफ भी पूरी शिद्दत से संघर्ष करना होगा।'

साभार : जन गर्जन मासिक माह जून अंक 10

दिल्ली विश्वविद्यालय में बी.एस.सी. (प्रोग्राम) के छात्र असमंजस की स्थिति में

दिल्ली विश्वविद्यालय के बी.एस.सी. (फिजिकल साईंस) और (एप्लाइड फिजिकल साईंस) के विद्यार्थी इस वर्ष भी भ्रम की स्थिति में है कि कहीं पिछले वर्षों की भांति इस वर्ष भी परीक्षा पास करने के लिये लागू मानक न बदल जायें और छात्रों की जो पुरानी परिस्थितियाँ थी ज्यों की त्यों न रह जाये।

दरअसल बी.एस.सी. (प्रोग्राम) को आरम्भ हुय यह तीसरा सत्र ही है। पिछले सत्र जब यह कोर्स शुरू किया गाय था तब न तो अध्यापकगण को इस कोर्स से सम्बन्धित जानकारी थी और न ही विद्यार्थियों को कि उन्हें पढ़ाना क्या हैं और पढ़ना क्या हैं। कोर्स से सम्बन्धित दिशा निर्देशिकाओं (गाईड लाईन) जनवरी और फरवरी में सम्बन्धित कॉलेजों में भेजी गयी और जीवन विज्ञान की प्रयोगशालायें काफी कॉलेजों में थी ही नहीं और इन सबके बाद न तो अध्यापक सिलेवर्स पूरा कर पायें और न ही कोर्स की उसकी आवश्यकताओं के हिसाब से पढ़ा पाए। परिणाम यह हुआ कि 60 फिसदी विद्यार्थी उत्तरी और दक्षिणी परिसर को मिलाकर फेल हुये। इतनी भारी संख्या में फेल हुये विद्यार्थियों को देखकर प्रशासन को अपनी गलतियों का एहसास हुआ और बाकी कोर्सों की तरह बी.एस.सी. (प्रोग्राम) में भी ई.आर. का प्रावधान करना पड़ा।

दूसरा सत्र भी इसी तरह गुजरा और विश्वविद्यालय प्रशासन ने अपनी पहले की गयी गलतियों से कुछ नहीं सीखा और इससे 45 फिसदी के करीब विद्यार्थी पूरे विश्वविद्यालय में फेल हुये। विद्यार्थियों ने भूख-हड़ताल की और ई.आर. वाला प्रावधान जारी रखने का आग्रह किया। विश्वविद्यालय प्रशासन ने प्रथम वर्ष के छात्रों को राहत दी परन्तु दोहरे मादण्ड के कारण बी.एस.सी. (प्रोग्राम) द्वितीय वर्ष के छात्रों को अनदेखा कर दिया और कहा गया कि 40 फिसदी संख्या कम है द्वितीय वर्ष के छात्रों को राहत देने के लिये।

कही न कहीं तो विश्वविद्यालय की कार्यपद्धति में है और उच्च पदों पर आसीन लोगों के गैर-जिम्मेदाराना रवैये है। हम सभी को ज्ञात है कि प्राथमिक विद्यालयों में भी नया कोर्स आरम्भ करने से पहले अध्यापकों को ट्रेनिंग दी जाती है। पर बी.एस.सी. (प्रोग्राम) जैसे कोर्स को शुरू करने से पहले कोई ट्रेनिंग अध्यापकों को नहीं दी गयी। जबकि इस कोर्स को पढ़ने वालों की कमी और समस्या है। छात्रों द्वारा इतने सारे सिलेवर्स को तीन वर्षों में पढ़ने के बावजूद आनर्स की तुलना में अवसर भी कम है। सूत्रों की माने तो इस कोर्स को शुरू करने के नाम पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से काफी फण्ड ले चुका है और उसमें धांधली की गयी। फण्ड की सम्बन्धित कॉलेजों तक नहीं पहुँचाया गया, जिससे वहाँ पर लैब अभी भी निम्न स्तरीय हैं।

इन सबको करने वाली बी.एस.सी. (प्रोग्राम) की चेयरमन डॉ. सविता दत्ता को प्रमोशन दिया गया। यह अनियमितताओं का खेल अभी तक जारी है और यह सब एड ऐसे केन्द्रीय विश्वविद्यालय में हो रहा है। जहाँ आस-पास और पूरे भारत वर्ष से विद्यार्थी अपने अच्छे भविष्य का सपना लेकर आते हैं। यह वाकई दुर्भाग्यपूर्ण हैं।

मनोज शर्मा (ए.आर.एस.डी. कॉलेज, डी.यू.)

AISB में शामिल होने के लिये निम्न फोन नं. पर संपर्क करें

दिल्ली : 9818885002, 9868779659, 9911671266 **मध्य प्रदेश : 09893830364,** **बिहार : 09430441878** **झारखण्ड : 09334011411**
पश्चिम बंगाल : 09433099637, **उत्तर प्रदेश : 09936020292** **मणिपुर : 09856081543** **आसाम : 09954575122**

अथवा अधिक जानकारी के लिये केन्द्रीय कार्यालय में संपर्क करें

*** ए.आई.एस.बी. पर अंग्रेजों द्वारा प्रतिबंध के कारण अनेक बार संगठन नाम बदलना पड़ा है**

Edited, Published by Amresh Kumar for AISB from 28, Gurudwara Rakab Ganj Road, New Delhi-1
Co-Editor: Manoj Sharma. Central Office : All India Students Bloc (AISB), 28, Gurudwara Rakab Ganj Road, New Delhi-1, Ph.: 23352273, Telefax : 23714131, E-mail: amresh_aisb@yahoo.in aisb_cc@yahoo.co.in